दैनिक जागरण

सोमवार, 1 दिसंबर 2014 : मार्गशीर्ष शुक्ल 10, 2071

हमें कर्मों का नहीं, कामना का त्याग करना चाहिए

बदलाव की आस

पुलिस महानिदेशकों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सालाना सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बिल्कुल सही कहा कि पुलिस को चुस्त-दुरुस्त, संवेदनशील और तकनीक से लैस होने की जरूरत है, लेकिन प्रश्न यह है कि यह काम होगा कैसे? पुलिस के आधुनिकीकरण और उसके कामकाज में सुधार लाने की बातें एक लंबे अर्से से हो रही हैं, लेकिन स्थितियां करीब-करीब जस की तस हैं। मुश्किल यह है कि राज्य सरकारें पुलिस सुधारों के मामले में तनिक भी सचेत-सक्रिय नहीं हैं और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि पुलिस सुधारों संबंधी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशोंपर अमल अभी भी नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में पुलिस सुधारों संबंधी कुछ दिशा-निर्देश दिए थे। उम्मीद यह की जा रही थी कि उन पर शीघ्र ही अमल होगा, लेकिन दो-तीन राज्यों को छोड़ दिया जाए तो अन्य राज्य इन दिशा-निर्देशों पर अमल करने में आनाकानी ही कर रहे हैं। इन स्थितियों में यह आवश्यक हो जाता है कि केंद्र सरकार राज्यों को इसके लिए विवश करे कि वे पुलिस सुधारों की दिशा में आगे बढ़ें, क्योंकि अब यह पूरी तौर पर स्पष्ट है कि राज्य सरकारें जानबूझकर पुलिस सुधारों को लागू करने से इन्कार कर रही हैं। दरअसल वे पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल करने की सुविधा का परित्याग करने के लिए तैयार नहीं। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के हिसाब से न तो शीर्ष पुलिस अधिकारियों के कार्यकाल को तय करने के संबंध में कोई प्रगति हुई है और न ही उनके मनमाने तबादलों को रोकने के मामले में। स्थितियां इसलिए और खराब हैं, क्योंकि राज्य सरकारें पुलिस के आधुनिकीकरण के मामले में भी ध्यान नहीं दे रही हैं। यह तब है जब पुलिस के समक्ष चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं। ज्यादातर राज्यों में पुलिस आवश्यक संसाधनों और आधुनिक तकनीक के अभाव से बुरी तरह जूझ रही है।

अपने देश में आबादी और पुलिस बल का अनुपात बहुत ही दयनीय है, बावजूद इसके इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे हैं कि पुलिस संख्या बल से मजबूत हो। पुलिस के समक्ष एक अन्य बड़ी समस्या प्रतिकूल कार्यदशाओं की भी है। पुलिसकर्मियों का बोझ हर दिन बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन उनकी कार्यदशाओं में कहीं कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। आखिर इन स्थितियों में यह उम्मीद भी कैसे की जा सकती है कि पुलिस उस तरह की बनेगी जैसी कि अपेक्षा प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पुलिस को संवेदनशील, आधुनिक, सजग, विश्वसनीय और तकनीकी रूप से कुशल बनाने के लिए बहुत भारी संसाधन जुटाने होंगे। यह दुखद है कि जब हर क्षेत्र में सुधार हो रहे हैं तब भारतीय पुलिस कुल मिलाकर उसी ढांचे में कार्य कर रही है जो अंग्रेजी सत्ता ने बनाया था। इस संदर्भ में इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि अंग्रेजों ने पुलिस के ढांचे का निर्माण इस तरह से किया था कि भारतीय जनता को आतंकित किया जा सके। पुलिस सुधारों को लेकर बहुत बातें हो चुकीं और यह साफ है कि केवल बातें करते रहने से हालात बदलने वाले नहीं हैं। चूंकि कानून एवं व्यवस्था राज्यों का विषय है इसलिए यह भी स्पष्ट है कि पुलिस सुधारों के संदर्भ में केंद्र के दबाव पर राज्य सरकारें इस तरह का रोना रो सकती हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र में अनावश्यक दखल दिया जा रहा है। इन स्थितियों में बेहतर यह होगा कि भाजपा शासित राज्य सरकारें पुलिस सुधारों की दिशा में अन्य राज्यों के समक्ष मिसाल पेश करें।

गनर की मांग

राज्य विद्युत अभियंता संघ के वार्षिक अधिवेशन में बिजली अभियंताओं द्वारा रखी गई नीली बत्ती और गनर की मांग के पीछे बेशक उनके अपने तर्क होंगे, लेकिन आम उपभोक्ता यह अवश्य जानना चाहेगा कि इससे सरकारी खजाने और आखिरकार उसकी जेब पर कितना भार पड़ेगा। उसके एवज में उसे भरपूर बिजली कब मिलेगी। वैसे, सिर्फ राज्य विद्युत परिषद ही नहीं कर्मचारी किसी भी विभाग के हों, अपने वार्षिक अधिवेशन में उन्हें सेवाशर्तों और सुविधाओं की मांग रखने का पूरा अधिकार है। जायज मांगों को पूरा भी किया जाना चाहिए किंतु ऐसी बेतुकी मांगों के पीछे का औचित्य नजर नहीं आता। सरकारी कर्मचारियों में पदनाम और सुविधाओं की चाह इधर बहुत बढ़ी है। वे सरकार के निकट रहते हैं और नेतागण उनकी मांग पूरी भी करते हैं लेकिन उत्तरप्रदेश की प्राथमिकता क्या है? जाहिर है, पर्याप्त नागरिक सुविधाएं। हर मकान को बिजली उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2016 में शहरों में 22 घंटे और देहात में 18 घंटे बिजली देने का वादा किया है। उनके सामने इसे निभाने की चुनौती भी है और यह भी कि पहले से ही भारी बिजली दरों की मार झेल रहे लोगों को और भार न सहना पड़े। यदि यह लक्ष्य पूरा होता हो तो किसी को सुविधाएं देने में किसी को क्या गुरेज हो सकता है। जनता भी बुरा नहीं मानेगी। जनता बेचारी तो अभी यही नहीं समझ पा रही कि बिजली जाने पर सब स्टेशन का फोन क्यों नहीं उठता। निश्चित तौर पर बिजली की कम उपलब्धता के कारण गर्मी के दिनों में अभियंताओं को आक्रोश झेलना पड़ता है। उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ती है लेकिन, इसके लिए पुलिस है। इसके लिए संसाधन जुटाने और अधिक बिजली उत्पादन की जरूरत है। दोषपूर्ण वितरण प्रणाली के छेद भरने की आवश्यकता है। बिजली विभाग में निचले स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों की भी कई जायज समस्याएं हैं। उन्हें भी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर काम करना पड़ता है। बिजली खराबी ठीक करने के लिए फटे दस्तानों के साथ खंभों पर चढ़ने वाले संविदा श्रमिक का बीमा अधिक जरूरी है या बेहतरीन वेतन पाने वाले अभियंता के लिए गनर! क्षमता से अधिक भार ढोने के कारण दगने वाले ट्रांसफार्मर बदलना ज्यादा जरूरी है या नीली बत्ती का इंतजाम करना। निर्णय सरकार को करना है और वह करेगी भी।

बड़े सुधारों का समय

तेज विकास के लिए सरकार से जरूरी सुधारों समेत पांच साल का रोडमैप बनाने की अपेक्षा कर रहे हैं लार्ड मेघनाद देसाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार अब छह माह से अधिक पुरानी हो चुकी है, लेकिन सवाल यही है कि हम इसकी शुरुआती प्रगति का आकलन किस रूप में किया जाए? इसमें दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर भारत की उम्मीदों को कहीं अधिक बढ़ा दिया है और लोगों को उन पर पूरा विश्वास भी है। आम चुनावों के दौरान उन्होंने जिस गतिशीलता और ऊर्जा-उत्साह के साथ कार्य किया था वह दुनिया के तमाम देशों की यात्राएं करने के बावजूद अभी भी बरकरार है। उनकी विदेश यात्राओं के क्रम में जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार और फिजी ही नहीं, बल्कि नेपाल और भूटान भी शामिल हैं। इन देशों की यात्रा के दौरान लोगों पर उनके जबर्दस्त प्रभाव को न केवल देशवासियों ने, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों ने भी महसूस किया। मोदी के जन्मदिवस पर चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग भारत दौरे पर आए और अब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारतीय गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के तौर पर भारत की यात्रा पर आ रहे हैं।

यदि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दें तो इससे पूर्व अन्य किसी भी नेता ने विदेशों में भारत की छवि बढ़ाने में इतना अधिक योगदान नहीं दिया। यहां इस पर भी विचार करना होगा कि इसके बावजूद भी मोदी के राजनीतिक विरोधी कहते हैं कि देश में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जिसे पश्चिमी देशों ने वीजा देने से कभी इन्कार किया हो। सच्चाई यही है कि मोदी ने न सिर्फ एशिया को लेकर नीतियों में नयापन दिखाया है, बल्कि अमेरिका के साथ भी भारत के रिश्तों को मजबूती देने का काम किया है। चीन के साथ मोदी सरकार ने गर्मजोशी जरूर दिखाई, लेकिन उतनी ही सतर्कता भी। भारत के संदर्भ में सीमाओं पर यदि चीन ने कोई भी आकस्मिक कार्रवाई अथवा अशांति फैलाने की कोशिश की तो जापान और अमेरिका हमारे लिए सुरक्षा का ढाल बन सकते हैं। संभवतः यही कारण है कि तटवर्ती क्षेत्रों में तेल की खोज के काम में भारत चीन के निकट पड़ोसी देश वियतनाम का सहयोग कर रहा है और इतना ही नहीं उसे नौसैनिक सहयोग-समर्थन भी प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान के साथ संबंध सुधार की दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हो पा रही है। हालांकि यह सब शुरुआती दिनों की बात है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत के साथ मित्रता कायम करने की अधिक अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लामाबाद में संसद के बाहर इमरान खान उनकी घेरेबंदी करने और विरोध-प्रदर्शनों में लगातार जुटे हुए हैं। कुल मिलाकर घरेलू मोर्चे की बात करें तो अभी भी इस बात की संभावना काफी अधिक है कि राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा को जीत मिलेगी। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में भी उसका परीक्षण होना है। यदि भाजपा इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करती है तो पार्टी की विश्वसनीयता में निश्चित ही वृद्धि होगी और कांग्रेस को अवश्य ही कुछ नया करने के लिए सोचना होगा।

आगामी चुनावों में जीत से भाजपा की प्रतिष्ठा और प्रभुत्व समूचे भारत में कायम हो जाएगा। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों में मिली जीत से पार्टी को काफी मदद मिली है। यदि झारखंड और दिल्ली में भी चुनाव परिणाम भाजपा के पक्ष में रहते हैं तो राज्यसभा में भी सरकार काफी मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी। इस समय जो बात सर्वाधिक जरूरी है वह यही कि आर्थिक सुधारों के काम को आगे बढ़ाया जाए। मोदी सरकार को अपना पहला बजट चुनावों के बाद बहुत कम समय में पेश करना पड़ा और इस कारण वह सुधारों की दिशा में बहुत काम नहीं कर सकी, लेकिन अब वित्तमंत्री अरुण जेटली ने दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों की बात कहनी शुरू कर दी है। इसके लिए जरूरी नहीं कि फरवरी के बजट में ही सब कुछ पेश किया जाए। अभी जिस बात की जरूरत है वह यही कि आगामी पांच वर्षों में अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार का रोडमैप अथवा खाका क्या होगा? वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की दिशा में आगे बढ़ना एक अच्छा संकेत है। ईंधन सब्सिडी पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही उर्वरक और जल सब्सिडी पर भी ध्यान देना होगा। बिजली की दरों को नए सिरे से निर्धारित करने की आवश्यकता है। रोजगार सृजन के लिए बुनियादी ढांचे में व्यापक कार्य करने होंगे। देश में अधिक लंबे समय तक मनरेगा की आवश्यकता नहीं है।

सरकार का असली परीक्षण विनिर्माण क्षेत्र में सुधार लाने से होगा। श्रम सुधारों की दिशा में तत्काल काम करना होगा और इसके लिए राज्यों के आंशिक कदमों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। भारत को कुछ ऐसी बड़ी विनिर्माण इकाइयों की जरूरत है जहां हजारों की संख्या में नहीं तो सैकड़ों की संख्या में रोजगार का सृजन हो सके। ऐसा करके हम जनसांख्यिकीय बढ़त का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों की संख्या में कम उत्पादक कार्यों से जुड़े लोगों को शहरी विनिर्माण केंद्रों तक लाना होगा। गरीबी से निजात पाने का यही रास्ता है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने यही किया है। भारत को कांग्रेस की दुविधापूर्ण नीति को छोड़ना होगा, जो अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में उदारीकरण लाने के बावजूद बुनियादी ढांचे के क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रही। इस बारे में संदेह यही है कि सरकार विपक्ष से सीधे टकराव को तैयार नहीं दिखती। संभवतः वह राज्यसभा में खुद के अधिक मजबूत होने का इंतजार कर रही है और ऐसा होने के बाद वह बड़े सुधारों की दिशा में आगे बढ़ेगी, लेकिन समय मूल्यवान है। अर्थव्यवस्था को 6.5 से 7 फीसद की विकास दर पर लाने के लिए बहुत कुछ किया गया है, लेकिन मोदी का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को 8 से 9 फीसद की विकास दर पर लौटाना है। यह लक्ष्य भूमि और श्रम बाजार में आमूलचूल सुधार किए बिना नहीं हासिल किया जा सकता। इस क्रम में राजकोषीय सुधार भी जरूरी हैं। सरकार की कर्ज देनदारी बहुत अधिक है। कारपोरेट बांड बाजार तभी बढ़ सकता है जब सरकार कुछ नए तौर-तरीके अपनाए।

राजकोषीय कमजोरी के चलते ब्याज की दरें बहुत अधिक हैं। हमें जल्दी से जल्दी संतुलित बजट पर काम करना होगा और विनिवेश के माध्यम से कर्ज में उल्लेखनीय कमी लानी होगी। यह सब शीर्ष स्तर की इच्छाशक्ति से जुड़ी हुई बातें हैं। इसके लिए हमें एक स्पष्ट रोडमैप तैयार करना होगा कि किस तरह भारत एकल अंकों में अथवा दोहरे अंकों में विकास हासिल कर सकता है। जीडीपी विकास की यह दर 8 फीसद से लेकर 11 फीसद तक हो सकती है। इसके लिए सार्वजनिक बनाम निजी स्वामित्व में नए सिरे से सामंजस्य बैठाना होगा। 1950 में सार्वजनिक क्षेत्र में तमाम नई इकाइयों की शुरुआत की आवश्यकता थी, लेकिन प्रथम 10 वर्ष अथवा उससे अधिक के बाद राष्ट्रीयकरण महज एक ढीला-ढाला विचार भर रह गया। यह सब तब हुआ जब तमाम एशियाई देश तेजी से विकास कर रहे थे। एक सफल आर्थिक शक्ति बनने के लिए इस बात पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। मेरे विचार से अच्छे दिन आने से पहले कठिन दिन आने चाहिए।

(लेखक प्रख्यात स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

देरी का नुकसान

◆ मोदी सरकार संभवत: राज्यसभा में खुद के अधिक मजबूत होने का इंतजार कर रही है और ऐसा होने के बाद वह बड़े सुधारों की दिशा में आगे बढ़ेगी, लेकिन समय मूल्यवान है

केंद्रशासित काशी

वाराणसी की विशिष्टता और सांस्कृतिक वैभव के लिए उसका केंद्रशासित होना जरूरी मान रहे हैं आर. विक्रम सिंह

एक विशिष्टता है वाराणसी की। यह विशिष्टता किसी पहचान की मोहताज नहीं है। यह हम देश के नागरिकों का दायित्व है कि इसे स्वीकार करें। अनादिकाल से एक मूल संस्कृति चली आती है। काशी ने उस सांस्कृतिक प्रवाह में अहम भूमिका अदा की है। उस समय विश्व में कोई और धर्म नहीं था। सभ्यता की उजास कहीं-कहीं दिखनी प्रारंभ हुई थी। तब की दुनिया में सिर्फ एक सर्वशक्तिमान ईश्वर हुआ करता था। वेदों के बाद के काल में काशी धर्म-संस्कृति का मुख्य पड़ाव बनी। काशी अलग है। इसीलिए कहा गया कि यह नगरी शिव के त्रिशूल पर बसी है। सिर्फ बनारसी साड़ी काशी की पहचान नहीं है। पर्यटन विकास की यहां असीम संभावनाएं हैं। कल्पना करें कि काशी सारनाथ सड़क मार्ग से कंबोडिया, बैंकाक से जुड़ गया है। अब सोचें कि बौद्ध यात्रियों की संख्या में कितनी अभिवृद्धि होगी? विकास के अनेक आयाम अभी सोचे भी नहीं गए हैं। शूलटंकेश्वर से गंगा अगर उत्तरमुखी होती हैं तो शिवकाशी के लिए ही। कोई और कारण नहीं था। भगीरथ चाहते तो सीधे निकल जाते। पर नहीं, वे ठिठके, रुके फिर उत्तर की दिशा में चलते हुए विश्वेश्वर के निकट क्षणमात्र को रुके, प्रणाम किया, बढ़ गए। पीछे गंगा का वेग था, लेकिन गंगा रुक गई, उन्हें शिव को स्पर्श जो करना था। कगार कटने लगे। चीख-पुकार मच गई। आर्तनाद सुनकर नए बन रहे तट पर शिव का आना हुआ। चरण-स्पर्श पाकर आह्लादित गंगा पुनः भगीरथ के पीछे चल पड़ीं। भगीरथ इसके बाद मंथर गति से चले। परिणामतः गंगा का पार चौड़ा होता गया।

आखिर हम अकिंचन किस प्रकार काशी का वैशिष्ट्य स्वीकार करें। काशी धर्म संस्कृति की नगरी सदा से रही है। तब भी थी जब 1193 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हजारों मठ-मंदिरों को ध्वस्त किया और हजारों काशीवासियों का बलपूर्वक धर्मपरिवर्तन कराया। उस गहन निराशा और अंधकार के काल में भी काशी की मूल जिजीविषा मृत नहीं हुई, संस्कृति की लौ जलती रही। विध्वंस होते मंदिरों की मूर्तियों को लिए काशीवासी भागते रहे, मरते रहे। कोई इतिहासकार उन बलिदानों की कथा नहीं कहता। वह श्यामवर्णीय ब्राह्मण जो ध्वंस हो रहे विश्वेश्वर मंदिर से शिवलिंग लेकर भागा, उसे थोड़ी ही दूर पर मुगल घुड़सवारों ने भालों से बींध दिया। रक्तरंजित शिवलिंग से ब्राह्मण का शव हटा शिवलिंग को चार बलिष्ठ अहीर युवक ले भागे। दो मारे गए। फिर तो यह बलिदानों की रिले रेस बन गई। ये घटनाएं लोककथाओं में जीवित हैं। फिरोज शाह तुगलक के जमाने में जब काशी में कोई मंदिर बचा ही नहीं था तब भी यह हमारी धर्म संस्कृति की नगरी रही है। अक्सर मुस्लिम बादशाहों ने मंदिर तोड़े, समाज को तोड़ा लेकिन जो समाज टूटा वह वापस नहीं लाया गया। कबीर उसी टूटे समाज की अभिव्यक्ति हैं जिसे कर्मकांडी ब्राह्मण समझ ही नहीं सके। उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। जहां चार्वाक तक का दर्शन स्वीकृत है वहां कबीर अस्वीकृत कर दिए गए। इसने विद्रोही कबीर को काशी का सच्चा प्रतिनिधि बनाया है। प्रायः सत्ताएं काशी की विरोधी रही हैं, अंग्रेजों ने अपने जमाने में नगर का सारा सीवर गंगा में खोल दिया। यह आस्थाओं पर परोक्ष हमला था।

काशी के कष्ट को मराठों ने महसूस किया। मुगल साम्राज्य के पराभव के बाद इंदौर के शासक मल्हारराव होल्कर के शासनकाल में काशी के धार्मिक-सांस्कृतिक वैभव को पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया आरंभ हुई, जो महारानी अहिल्याबाई होल्कर के काल में शिखर पर पहुंची। तब तक अंग्रेजों का काल आरंभ हो जाता है। गुलामी के इस दूसरे दौर में अंग्रेजों ने मंदिरों को बख्स दिया। महारानी अहिल्याबाई का काल काशी के लिए संजीवनी बना, लेकिन बहुत कुछ करना रह गया था। वाराणसी को केंद्रशासित राज्य बनाने की मांग सदियों से हुए अन्याय के प्रतिकार के साथ-साथ काशी की विशिष्टता के स्वीकार का उद्देश्य भी लिए हुए है। कई मित्रों ने कहा कि यह असंभव है। इसके लिए न राज्य न केंद्र सरकार, कोई तैयार नहीं होगा। हो सकता है। लेकिन अन्य केंद्रशासित राज्य कैसे बने हैं, यह भी देख लिया जाए। 10 लाख आबादी का चंडीगढ़ केंद्रशासित राज्य सिर्फ इसलिए बन गया कि पंजाब हरियाणा के बीच स्वामित्व के विवाद को स्थगित किया जा सके। पांडिचेरी जो 1947 से पहले फ्रेंच कालोनी था, अपनी फ्रेंच संस्कृति, वास्तु स्थापत्य की विशिष्टता की रक्षा के लिए केंद्रशासित बनाया गया। यदि तुलना करें तो हम पाएंगे कि वाराणसी को केंद्रशासित राज्य बनाने का तर्क इन दो राज्यों के लिए दिए गए तर्कों की तुलना में कहीं अधिक सबल है। काशी तो एक सभ्यता का केंद्रबिंदु है। दुनिया के प्राचीनतम नगरों में से एक, विश्व के तीन महान धर्मों का केंद्र यह गंगा व शिव का स्थान भी है। वेटिकन सिटी, मक्का शरीफ तो एक धर्म के हैं। यहां धर्मों का उद्गम है। अब उम्मीदें जगी है कि काशी धर्म, संस्कृति, कला ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ते हुए आध्यात्मिक गुरु का स्थान ग्रहण करे। उम्मीदें तब भी जगी होंगी जब मुगलों के बाद मल्हारराव होल्कर का शासन आया था। फिर 50 वर्षों तक अहिल्याबाई का शांतिपूर्ण उपलब्धि भरा शासन रहा। अंग्रेज आए फिर अंग्रेजों के बाद आजाद भारत में सब कुछ सेक्युलर हो गया। आज राजनीतिक दिशा परिवर्तन के साथ काशी पुनः हमारी आशाओं का केंद्र बन गई है। ये उम्मीदें सिर्फ नाली, सड़क, खड़ंजे व नागरिक सुविधाओं की मात्र नहीं है, बल्कि उस सांस्कृतिक वैभव के लिए है जो काशी ने गुप्तकाल के बाद फिर कभी नहीं देखा। नाना फड़नवीस ने टीपू सुलतान के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ इसलिए दिया कि विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होने देने में अंग्रेज सहयोग दें। शिवाजी अपने राज्याभिषेक के लिए काशी से गागा भट्ट को बुला भेजते हैं। शेष भारत काशी और शिव को एकाकार एकरूप देखता है।

अगर काशी को वैशिष्ट्य प्रदान करने के लिए इसे केंद्रशासित प्रदेश का स्तर दिया गया तो यह काशी पर कोई एहसान न होगा, बल्कि काशी को उसका स्तर प्रदान करने की दिशा में एक प्रयास होगा। अगर ऐसा हुआ तो बहुत सी बातें अपने आप बदलनी आरंभ हो जाएंगी। काशी के प्रति नए सत्ता प्रतिष्ठान की सोच में परिवर्तन उस सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा को इंगित करेगा, जो राष्ट्र का भविष्य है।

(लेखक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं)

response@jagran.com

नई उम्मीदें

◆ अब उम्मीदें जगी हैं कि काशी धर्म, संस्कृति, कला, ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ते हुए आध्यात्मिक गुरु का स्थान ग्रहण करे

ऊर्जा
सीखने की आदत

सिखाना सभी चाहते हैं, पर स्वयं सीखना कोई नहीं चाहता। जो सिखाता है वह भी महापुरुषों की सीख को नहीं मानता है। उसका मानना होता है कि उसने जो जानकारी प्राप्त की है वह पर्याप्त है और उसे अपने व्यवहार में, चरित्र में ढालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए, क्योंकि अब वह ऐसा ज्ञाता है जिसे कुछ सीखने या सीखे हुए पर अमल करने की कोई जरूरत नहीं है। वह बेचारा यह नहीं जानता है कि उसके ज्ञाता होने का यह झूठा अहंकार उसके आध्यात्मिक उन्नयन में कितना अवरोध उत्पन्न कर रहा है? हम भक्तों-संतों और महापुरुषों की जीवनियों और उनके कृतित्व को बचपन से पढ़ते-सुनते रहते हैं, पर हमारा यह पढ़ना-सुनना तोते की तरह राम-राम कहना है। काश! हम उनकी सीख को समझ पाते, उसे अपने आचरण में उतार पाते।

गोस्वामी तुलसीदास ने 'विनय-पत्रिका' में अपनी दुर्बलताओं को बताते समय यह भी कहा है- 'सीख देता हूं, सिखाया हुआ नहीं मानता।' तुलसीदासजी ने ऐसा कहा है, पर यह सत्य नहीं है। जिस व्यक्ति ने वेदों, पुराणों, इतिहास, साहित्य आदि विविध स्रोतों से तथ्यों को ग्रहण कर रामचरितमानस जैसी कालजयी रचना हमें दी है, वह किसी का सिखाया नहीं मानता था, इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है? यथार्थ बात तो यह है कि अपने बहाने उन्होंने मनुष्यमात्र की इस एक बड़ी कमजोरी की ओर इंगित किया है और कहा है कि जो सीखने के लिए तैयार नहीं है उसे सिखाने का भी अधिकार नहीं है। तुलसी के इस कथन को पढ़ा-सुना तो अनेक लोगों ने होगा, पर इसके संकेत को अत्यल्प लोगों ने ही समझा होगा। साधारण मनुष्य दूसरों की जरा-सी गलती का तो बखान करने लगता है, पर अपनी पहाड़-सी दुर्बलता को भी जानने का प्रयास नहीं करता और यदि उसे जान भी ले तो उसे स्वीकार करने का साहस उसमें नहीं होता। तुलसीदास की 'विनय-पत्रिका' का एक-एक पद, उसका एक-एक शब्द अध्ययन-मनन करने योग्य है और उससे प्राप्त संकेतों से अपनी दुर्बलताओं को जानने-सुधारने की आवश्यकता है। मगर मुश्किल यह है कि हम अपने ऋषियों, भक्तों, संतों, महापुरुषों आदि की बातों में निहित संकेतों को समझने-जानने का प्रयास ही कहां करते हैं?

◆ डॉ. सरोजनी पांडेय

जागरण Junction
AAPKI AWAAZ, AAPKA BLOG
www.jagranjunction.com

जन्मदिन का मतलब

जन्मदिन और नया साल। इन दो मौकों पर ऐसा प्रतीत होता है मानो अनायास ही सिर समय की दीवार से जा टकराया हो। मुझे लगता है जन्म दिन और नया साल दोनों ही मौकों को भुनाने का चलन 80 के दशक में भौतिकता का प्रभाव बढ़ने के साथ हुआ। पहली जनवरी यानी नए साल की शुरुआत में कुछ न कुछ अलग नया करना है, इसकी धुन समाज के निचले स्तर पर भी सवार होनी शुरू हुई। इसी के साथ सामान्य वर्ग के लोग भी अपने बच्चों का जन्मदिन शानदार तरीके से मनाने लगे। राजनीति में पैसों और ग्लैमर की दुनिया के लोगों का प्रभाव बढ़ने के साथ जन्मदिन सुर्खियां बटोरने लगी। ग्लैमर की दुनिया में तब के सुपर स्टार राजेश खन्ना के बारे में सुना है कि उनके सुनहरे दौर में जन्म दिन पर ट्रकों में भर-भर कर फूल उनके बंगले में पहुंचते थे, लेकिन कालचक्र में जब उनके सितारे गर्दिश में चले गए तो उनके जन्मदिन को याद रखने वाला भी कोई न बचा। -तारकेश कुमार ओझा

पूरा ब्लॉग पढ़ने के लिए यथावत टाइप करें : http://bit.ly/1y8x63D

छात्रों के साथ दुर्व्यवहार

लोकतांत्रिक संघर्षो पर छात्रों की मांगें जायज हैं। बनारस में छात्र-नेताओं पर हुए लाठी चार्ज की निंदा की गई। दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी हुई। एक तरफ बनारस के सांसद और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परदेस में पराए लोगों को भारत बुलाकर यहां की नर्सरी में पढ़ने का प्रलोभन बांट रहे थे और इधर उन्ही के संसदीय क्षेत्र बनारस में भारत का संचार-सक्षम मेधावी युवा पुलिस से पिट रहा था। आस्ट्रेलिया गए पिछले दिनों भारतीय छात्रों पर अपमान भरे नस्ली और रंगभेदी अपराध पर भारतीय प्रधानमंत्री की खामोशी से संवेदनहीनता का दंश अभी ठिठका ही था कि बनारस में छात्रों के उभार, प्रतिवाद के अधिकार को कुचल देने की हताश कोशिश में अविवेकपूर्ण हिंसा का सहारा लेकर सरकार निरंकुश और बर्बर दमन का आत्मघाती कदम उठा बैठी।

-यतीन्द्र नाथ चतुर्वेदी

पूरा ब्लॉग पढ़ने के लिए यथावत टाइप करें : :http://bit.ly/1uW2wD7

पाठकनामा
pathaknama@nda.jagran.com

नेताओं पर नकेल

काले धन का कारोबार शीर्षक से लिखे लेख में संजय गुप्त ने विदेशों से कहीं अधिक काला धन देश में होने की बात कही है और इसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की अपेक्षा की है। उन्होंने भ्रष्टाचार का एक बड़ा ठिकाना राजनीति को बताया है। इससे साफ है कि विदेशों और देश में जमा काले धन को निकालने के लिए तमाम उपायों-प्रयासों के साथ-साथ राजनीतिक और चुनाव सुधारों पर भी जोर देने की आवश्यकता है। राजनीतिक चंदे में मिली रकम को न केवल पारदर्शी बनाया जाए, बल्कि राजनीतिक दलों और नेताओं पर और अधिक नकेल कसी जाए, ताकि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लग सके और काले धन की जरूरत को खत्म किया जा सके।

प्रवीण कुमार, जेएनयू, दिल्ली

मोदी की मेहनत

मोदी ने जब राष्ट्रीय राजनीति में कदम नहीं रखा था तब भी राजनीतिक चर्चायें उनके बगैर अधूरी रहती थीं। अब तो वे स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री का गौरव प्राप्त कर चुके हैं। राजनीति के अखाड़े में कांग्रेस को बुरी तरह धूल चटा चुके मोदी ने अपने अलग अंदाज से गांधी, पटेल, नेहरू और इंदिरा गांधी तक को याद करने के मामले में ऐसा दांव चला कि कांग्रेस हर बार निरुत्तर ही रही। देश की सबसे पुरानी पार्टी में विकल्पों का अभाव कहा जाए या फिर एक परिवार की विरासत का चलन, मोदी को चुनौती देने के लिए जब-तब कांग्रेसजन राहुल के नाम को ही आगे बढ़ा देते हैं और जब बात नहीं बनती है तो प्रियंका लाओ के नारे सुनायी पड़ जाते हैं। कांग्रेसीजनों को यह मंथन अवश्य करना चाहिए कि आज मोदी जिस ऊंचाई पर हैं यह ऊंचाई उनकी स्वयं की मेहनत का फल है।

vandanalkowest@gmail.com

संस्कृत की उपेक्षा क्यों?

यह सर्वविदित है कि सत्य सदैव एक रूप में स्थित रहता है। वह किसी भी काल, किसी भी युग व किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता। जब सांस्कृतिक विरासत संस्कृत में निहित है फिर भी संस्कृत की उपेक्षा क्यों? अगर कक्षा में 40-50 छात्र हैं और उनमें से 10-12 छात्र भी संस्कारों को धारण करते हैं या कुमार्ग से सुमार्ग की ओर मार्ग प्रशस्त करते हैं तो देश का भविष्य बहुत हद तक सुरक्षित रह सकता है। छात्र किसी भी देश की सबसे मूल्यवान पूंजी होते हैं। सभी चाहते हैं कि मेरा बच्चा सुसंस्कारित हो, लेकिन कैसे?

एसएस शर्मा, पलवल

सार्क का उद्देश्य

सार्क सम्मेलन पिछले 30 सालों में कुछ खास असर नहीं दिखा पाया है। इस बार नेपाल में 18वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सार्क राष्ट्राध्यक्षों को आश्वस्त करने और उनमें विश्वास पैदा करने की कोशिश की और इस मौके पर उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे को भी उठाया। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक प्रमुख समझौतों का प्रस्ताव भी रखा जिनमें ऊर्जा, रेल और सड़क आदि प्रमुख हैं। इन समझौतों से सभी दक्षिण एशियाई देश सहमत थे, लेकिन पाकिस्तान इन समझौतों पर सहमत नहीं हुआ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने इसका कारण अपने बीच आंतरिक बातचीत का न होना बताया। इससे ये समझौते अधर में लटके दिखाई दे रहे हैं। सार्क का उद्देश्य तभी सार्थक हो सकता है जब पास -पास होने को साथ -साथ होने में बदल जाए।

राहुल शर्मा, नोएडा

पुरुषार्थी बनें, अंधविश्वासी नहीं

हृदय नारायण दीक्षित का ज्योतिष और विज्ञान संबंधी लेख, गणित ज्योतिष एवं फलित ज्योतिष में भेद करने में असक्षम दिख रहा है। गणित ज्योतिष पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। गृह, नक्षत्र, मौसम आदि में परिवर्तन को गणित ज्योतिष की सहायता से पहले ही जाना जा सकता है। यह विशुद्ध वैज्ञानिक सोच है, मगर गृह दशा आदि के कारण आपके भाग्य का उदय और अस्त होना आधारहीन कल्पना मात्र है। वेदों में कर्म फल व्यवस्था का विधान है जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। गृह आदि जड़ पदार्थों से मनुष्य को बिना कर्म फल मिलना वेदों की अवधारणा के विपरीत मत है। वेद व्यक्ति को जीवन में पुरुषार्थी बनने का सन्देश देते हैं, फलित ज्योतिष चमत्कार में विश्वास करने का झांसा देने के समान है। पुरुषार्थी बनें अंधविश्वासी नहीं।

drvivekarya@yahoo.com

जनपथ

समधी लालू बन रहे सिंह मुलायम संग,
आगे-आगे देखिए इस रिश्ते का रंग।
इस रिश्ते का रंग और उस पर याराना,
राजनीति में खूब जमेगा ये समध्याना।
संसद में परिवार की धमक ही क्या कम थी,
अब तो क्रिकेट टीम बना लेंगे ये समधी।

-ओमप्रकाश तिवारी

ट्वीट ट्वीट

आतंकवादियों को पनाह-संरक्षण देने के लिए भारत पाकिस्तान पर आरोप लगाता रहता है। अब बांग्लादेश भी कुछ इसी तरह जमात-उल-मुजाहिदीन को पश्चिम बंगाल में संरक्षण मिलने की बात कह सकता है।

गौरव सावंत @gauravcsawant

सोनिया गांधी ने भारत को जो क्षति पहुंचाई है उसका हिसाब लगा पाना मुश्किल है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर के देशों में विस्तृत दौरा अभियान चलाकर इसकी कुछ क्षतिपूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत को दुनिया में उभारने का काम कर रहे हैं।

नवरूप सिंह @s_navroop

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आपको लगता है कि भाजपा पश्चिम बंगाल में अगले विधानसभा चुनाव तक मुख्य मुकाबले में आ जाएगी?

आज का सवाल

क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की नसीहत के बाद देश में पुलिस के कामकाज में सुधार की राह निकलेगी?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें

Y-हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।